

- वर्ष : 15
- अंक : 21
- सोमवार, 07 से 13 जुलाई 2025
- मूल्य : 5 रूपए
- रु. 250 वार्षिक

दिल्ली में आधार
के लिए हों सख्त
नियम :
उपराज्यपाल

1300 राजनयिकों
और कर्मचारियों की
छंटनी से विदेश विभाग
में मचा हड़कंप



www.ncrsamacharlive.in

BY C.R.O. TEAM

twitter-@ncrsamacharlive

भारत का नं.

साप्ताहिक
समाचार पत्र

मेट्रो इन दिनों फिल्म ने वीकएंड पर किया कमाल

12

प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में 51 हजार युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र

निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर सरकार का जोर : मोदी

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विनिर्माण क्षेत्र को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा है कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर भी जोर दे रही है।श्री मोदी ने शनिवार को यहां वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से रोजगार मेले में 51 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद यह बात कही। इन युवाओं को सरकार के विभिन्न विभागों और संगठनों में नियुक्त किया गया है।

प्रधानमंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा, आज भारत की एक बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बहुत बड़ी संख्या



में नई जॉब्स बन रही हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को गति देने के लिए इस वर्ष के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे देखते हुए सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने पर अच्छा खासा जोर दे रही है। उन्होंने

कहा, भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्क्रीम रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। लोकतंत्र और युवा आबादी को भारत की असीमित शक्ति बताते हुए श्री मोदी ने कहा, आज

51 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान...राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज दुनिया मान रही है कि भारत

के पास दो असीमित शक्तियाँ हैं। एक 'डेमोग्राफी', दूसरी 'डेमोक्रेसी'। यानि सबसे बड़ी युवा आबादी और सबसे बड़ा लोकतंत्र। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप और अनुसंधान का एक सिस्टम मिलकर युवाओं का सशक्तिकरण कर रहा है।

प्रधानमंत्री ने कहा, स्टार्टअप, इनोवेशन और रिसर्च का जो इकोसिस्टम आज देश में बन रहा है... वो देश के युवाओं का सामर्थ्य बढ़ा रहा है।अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि भारत को सबसे अधिक समानता वाले देश की श्रेणी में रखा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है... बीते दशक में भारत के 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को वेल्फेयर स्कीम्स के दायरे में लाया गया है।आज वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी वैश्विक संस्थाएं भारत की प्रशंसा कर रही हैं।

रोजगार के लिए नई योजना की शुरुआत

पीएम मोदी ने कहा, 'आप सबको पता है कि 2 दिन पहले ही मैं 5 देशों की यात्रा से लौटा हूँ। हर देश में भारत की युवाशक्ति की गूंज सुनाई दी। इस दौरान जितने भी समझौते हुए हैं, उनसे देश और विदेश, दोनों जगह भारत के नौजवानों को फायदा होना ही है।'

नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत सरकार का जोर प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्क्रीम को मंजूरी दी है- रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15 हजार रुपए देगी, यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी।



स्विगटेक ने पहला
विवलडन खिताब जीता

कृषि वैज्ञानिक
बनकर संवारे भविष्य

इस्माईल खान

आईआईटी दिल्ली में अत्याधुनिक एमआरआई अनुसंधान केंद्र की शुरुआत



एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने मेडिकल इमेजिंग के क्षेत्र में शोध के लिए अपने परिसर में एक आधुनिक एमआरआई अनुसंधान सुविधा का शुभारंभ किया है। यह केंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस (आईआई) पहल के तहत स्थापित किया गया है। इसका उद्घाटन आईआईटी दिल्ली के निदेशक प्रो. रंगन बनर्जी ने किया। इस केंद्र में 1.5 टेस्ला क्षमता की क्लिनिकल-ग्रेड एमआरआई मशीन लगाई गई है।

यह सुविधा भारत के किसी भी प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थान में अपनी तरह की पहली है जो पूरी तरह शोध और पढ़ाई के लिए समर्पित है। यह पारंपरिक अस्पताल-आधारित एमआरआई मशीनों से अलग है,

और इसका उद्देश्य चिकित्सा छवियों (इमेजिंग) के क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देना है।

प्रो. रंगन बनर्जी ने इस अवसर पर कहा कि यह नई सुविधा आईआईटी दिल्ली में मेडिकल इमेजिंग और हेल्थकेयर में विज्ञान, इंजीनियरिंग और चिकित्सा के संगम पर नया ज्ञान विकसित करने में सहायक होगी। यह सुविधा आईआईटी दिल्ली के सेंटर फॉर बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में स्थित है। शुरुआती चरण में यहां नकली मॉडल (फैंटेम्स) पर शोध किया जाएगा। नियामक मंजूरी मिलने के बाद, स्वयंसेवकों पर चिकित्सा अध्ययन भी किए जाएंगे। इसके अलावा, यह केंद्र मेडिकल इमेजिंग पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक प्रशिक्षण मंच के रूप में भी काम करेगा।

बिहार मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण

चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर जताई आपत्ति

एनसीआर समाचार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को बिहार में जारी मतदाता विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मामले में सुनवाई हुई। कांग्रेस, टीएमसी, राजद, सीपीआई (एम) समेत कई विपक्षी पार्टियों ने बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण पर रोक लगाने की मांग की। हालांकि, चुनाव आयोग ने याचिकाओं पर आपत्ति जताई और कहा कि चुनाव आयोग का सीधे मतदाताओं से रिलेशन है।

जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। पूर्व अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चुनाव आयोग की तरफ से पक्ष रखा, जबकि कपिल सिब्बल और गोपाल शंकर नारायण ने



याचिकाकर्ताओं की ओर से दलील दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची को संशोधित करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं एक ऐसे मुद्दे को उठाती हैं, जो लोकतंत्र की जड़ों को प्रभावित करता है, जिसमें वोट देने का अधिकार शामिल है।

याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद, जस्टिस सुधांशु धूलिया और जॉयमाल्या

आयोग के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) की शक्ति को चुनौती दे रहे हैं, बल्कि इसकी प्रक्रिया और समय पर भी सवाल उठा रहे हैं। हालांकि, चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कोर्ट से इस स्तर पर एसआईआर प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, संशोधन प्रक्रिया पूरी होने दें, फिर पूरी तस्वीर देखी जा सकती है। इस पर बेंच ने कहा कि एक बार मतदाता सूची संशोधित होकर विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी, तो कोई भी कोर्ट इसे नहीं छुएगा।

याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सभी याचिकाओं पर नहीं जाएंगे। हम मूल कानूनी सवालों पर बात करेंगे। सबसे पहले एडीआर की तरफ से वकील गोपाल शंकर नारायण ने दलील रखी।

याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि मतदाता गहन पुनरीक्षण में 11 दस्तावेजों की अनिवार्य किया गया है। यह पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण है। एसआईआर का फैसला न तो आरपी एक्ट में है और न ही इलेक्शन रूल में है।

खानपुर गांव के पक्के मकानों पर चला बुलडोजर, नहीं मिला उचित मुआवजा



कोर्ट के आर्डर के मुताबिक 43 दुकानों और 11 मकानों को तोड़ा गया। इसके बाद खानपुर गांव की जमीन उत्पन्न हो दे दी गई। स्थानीय पीड़ित लोगों का कहना है कि, DMRC ने कोर्ट के छुड़ियों का फायदा उठाते हुए कार्रवाई की है। उन्हें बड़े ही शार्ट नोटिश पर खली करने को कहा गया। पहले हुई बातचीत के मुताबिक उनके जमीन का

मुआवजा 3.70 लाख प्रति गज के हिसाब से मिलना तय हुआ था जो कि, 2 हजार रुपए प्रति गज पर आकर खत्म हुआ है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि, यह उनके जमीन और घर का उचित मुआवजा नहीं है। मुआवजे की राशि अभी तक जमीन मालिकों को नहीं दी गई है, उसके लिए भी 45 दिनों के बाद प्रोसेस शुरू किया जाएगा।

एनसीआर समाचार पत्र के स्वामित्व/प्रकाशन परिवर्तन के संबंध में आवश्यक सूचना

एनसीआर समाचार पत्र के समस्त पाठकों तथा समाचार पत्र के साथ जुड़े समस्त पत्रकारों, व्यावसायिक संयोजक, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि गत वर्षों से श्री बलबीर सिंह के नेतृत्व व स्वामित्व में चले आ रहे वर्तमान एनसीआर समाचार पत्र का प्रकाशन व स्वामित्व मो. हनीफ, पुत्र श्री इस्माईल खान मास्टर जी, संगम विहार के स्वामित्व व नेतृत्व में हो रहा है। अतः भविष्य में समस्त प्रकार की व्यावसायिक, कानूनी एवं सामाजिक गतिविधियों के संचालन हेतु मो. हनीफ/बु नए कार्यालय जी-12/276, संगम विहार, नई दिल्ली-110062, दूरभाष (मोबाइल) 9210761111 सम्पर्क करें।

जलमग्न हुआ संगम विहार का शूटिंग रेंज और और रतिया मार्ग

नमिता चौहान

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में बरसात के कारण शूटिंग रेंज मार्ग पर जलभराव की स्थिति मानसून के दौरान बार-बार उत्पन्न होती है। जलभराव की स्थिति का मुख्य कारण नालियों की कमी, व्यवस्था की न्यूनता और ड्रेनेज इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। बारिश के समय सड़कें कीचड़, गड्ढे, और ट्रैफिक जाम में बदल जाती हैं, जिससे स्थानीय व्यापार, राहगीरों और ट्रैफिक को काफी असुविधा होती है। इस समस्या को स्थायी रूप से हल करने के लिए गहरी ड्रेनेज योजनाएं और उचित जल निकासी इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है।

मुख्य कारण
प्राकृतिक ड्रेनेज अव्यवस्था: 90% से अधिक क्षेत्र कंक्रीट से ढका है, बारिश का पानी जमीन में नहीं समा पाता, इसलिए सड़क पर



इकट्ठा होता है।

निर्माण और नालियों की कमी: निर्माण कार्यों के बाद भी ड्रेनेज सिस्टम तैयार नहीं किया गया, जिससे पानी कहीं से निकल ही नहीं पाता।

जलभराव की समस्या मानसून के हर दौर में होती है-स्थानीय लोग कहते हैं, बारिश होते ही पानी भर जाता है स्थानीय व्यापार और ट्रैफिक प्रभावित

दुकानदारों की शिकायतें: स्थानीय निवासियों ने बताया कि नालियों का अभाव होने से गंदा पानी, किचन या बाथरूम का पानी सीधे सड़क पर बहता है, जिससे गंदगी और स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ जाते हैं।

रतिया मार्ग और शनि बाजार रोड पर हल्की बारिश में ही गड्ढे बन जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक प्रभावित होता है और राहगीरों को परेशानी होती है

संगम विहार बीजेपी विधायक कार्यालय पर हुआ हमला

कार्रवाई में लापरवाही करने पर थाना अध्यक्ष पर हुई कार्रवाई

नमिता चौहान

दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार में बीते हफ्ते पानी के बोर को लेकर काफी हंगामा हुआ। विधायक चन्दन कुमार चौधरी ने बताया कि, संगम विहार के एफ-2 क्षेत्र में अवैध पानी के बोर पर कार्रवाई की गई, जिसके बाद स्थानीय जनता ने मौजूदा भाजपा विधायक चन्दन चौधरी पर पैसे न मिलने पर पानी के कनेक्शन को काटने का आरोप लगाया और विधायक कार्यालय पर हमला बोल दिया, कुर्सियाँ और अंडे फेंके, और कार्यलय प्रभारी पर हमला किया।

विधायक चंदन कुमार चौधरी ने बातचीत में बताया कि, इस मामले में जब उचित कार्रवाई में संगम विहार थाना अध्यक्ष कुमार संतोष ने लापरवाही दिखाई तो विधायक ने कानूनी करवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को लाइन हाजिर करवा दिया।

सोमवार को दोपहर करीब 2 बजे जब विधायक अपने दफ्तर पर मौजूद नहीं थे उस वक्त, जनता ने विधायक कार्यालय पर हमला किया, जिस दौरान अंडे और पत्थर फेंके गए, साथ ही कुर्सियाँ उठाकर



विधायक के आरोप

पानी के बोर के कनेक्शन से पानी का अवैध प्लांट चलाया जा रहा था। सोनिया विहार के मुफ्त पानी के पैसे लेकर बेचने का गलत काम किया जा रहा था। होशराम यादव नामक व्यक्ति बोर पर अवैध कब्जा कर के बैठा था। विधायक कार्यालय पर हमला करने वाली जनता एक ही परिवार की थी। महिलाओं ने हमला किसी के बहकाने पर किया था। पानी का कनेक्शन काटा नहीं गया है बल्कि, सप्लाई को बढ़ाने के लिए उस पर विकास का काम किया जा रहा है। विधायक ने यह भी कहा कि, इस मामले में उनका कोई हाथ नहीं है, जो भी कार्य पानी के बोर पर किया जा रहा है वो सब जल बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। जनता द्वारा लगाए गए आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। साथ ही विधायक ने यह भी कहा कि, इस मामले में सभी हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी और अपराधियों को सजा दिलावाई जाएगी।

स्थानीय लोगों का आरोप

स्थानीय लोगों का कहना है कि विधायक कार्यालय में जाकर शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया गया, लेकिन स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। लोग यह भी बता रहे हैं कि विधायक का नाम लेकर कुछ अनुज्ञापिबिहीन कर्मचारी या दलाल लोगों से अवैध शुल्क वसूल रहे हैं। 'हम मुफ्त पानी की सप्लाई पर निर्भर हैं, पर अचानक बिना कोई सूचना/समझौते के कनेक्शन काट दिए गए। विधायक ने स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया। वही, कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि विधायक का नाम केवल वसूली के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, असली जिम्मेदार व्यक्ति अन्य हैं।

SHO हुए लाइन हाजिर

विधायक कार्यालय पर हुए हमले में FIR दर्ज होने के बाद भी जब कई दिन बीत जाने पर कार्रवाई नहीं हुई तो विधायक ने संगम विहार थाना अध्यक्ष कुमार संतोष के खिलाफ बड़े अधिकारियों से शिकायत की, जिसके बाद उन्हें लाइन हाजिर किया गया और अब संगम विहार में नए थाना अध्यक्ष को लाने की तैयारी की जा रही है।

फेकी गई, कार्यकर्ताओं से मारपीट भी की गई। जैसे ही हमले की सूचना विधायक को मिली, फौरन उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हंगामे और हमले के दौरान ही पुलिस फोर्स वहां पहुंची साथ ही संगम विहार थाने के रलड और अन्य पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंचे।

पुलिस प्रशासन ने मामले को शांत करवा दिया। कुछ देर बाद विधायक भी मौके पर पहुंचे। इस मामले में जब उउफ समाचार की संवाददाता उमिता चौहान ने विधायक चन्दन चौधरी से बात की तो कई अन्य पहलू खुलकर सामने आए।

एनसीआर समचार,
साप्ताहिक समाचार पत्र में
विज्ञापन के लिए संपर्क करें।

कार्यालय :
12/276, संगम विहार
नई दिल्ली- 62

फोन :
9210761111

यहां से जाने दो

मार्फी मानें नंगा। कहा-
वीडियो मत बनाओ, मुझे
यहां से जाने दो। साथ में मौजूद शादीशुदा महिला
दुपट्टे से अपना चेहरा छिपाती रही। मामला शुक्रवार
रात रश्मिकपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव कैलाचन-
स्थित शकना का है। इसका वीडियो आज सामने
आया है। मामले सामने आने के बाद पार्टी ने राहुल
बाल्मीकि को पार्टी से निष्कासित कर दिया। वीरियं
वायरल होने के बाद से राहुल बाल्मीकि फरार हैं।
गुरुवार शुक्रवार शाम गांव कैलाचन स्थित रश्मिनान के
पास लोगों ने एक कार खड़ी देखी।

जेल से बाहर आते ही शेर अली जाफरी ने फिर फेंका लालच का जाल आधी फीस मे अब दे रहे हैं छात्र-छात्राओं को एडमिशन

राजु, उत्तर प्रदेश: शहर के कुख्यात फर्जी डिग्री घोटाले में जेल जा चुके शेर अली जाफरी और उनका बेटा फ़िरोज जाफरी एक बार फिर से विवादों में हैं। करीब 9 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद हाल ही में जमानत पर रिहा हुए शेर अली ने एक बार फिर वही पुराना खेल शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि डी.फार्मा और बी.फार्मा में दाखिले के नाम पर छात्र-छात्राओं को लुभाने के लिए अब वे आधी फीस के आकर्षक विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करा रहे हैं। यह वही शेर अली जाफरी है, जिस पर फर्जी डिग्री देने, फजीवांदा करने और करोड़ों की ठगी का गंभीर आरोप है। उनके खिलाफ प्रापर्टी जब्तीकरण की

वर्ष 1988 से खुसरो मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा संचालित

खुसरो कालेज

स्वीपर रोड सी०बी० गंज, चरली

फोन नं.-7417507162,8923928009

COURSES OFFERED :

B.A. | B.Sc | B.Com

B.BA | BCA | M.com

M.Sc
(Chemistry physics, Zoology, Botany, Mathematics)

M.A.
(English, Hindi, Economics, Sociology, Political Science, Urdu, Education, History)

I.T.I.
(Fitter, Electrician, Copa, Welder)

नोट:- इस वर्ष आधी फीस पर प्रवेश



कार्रवाई तक चल रही है, मगर हैरानी की बात ये है कि जेल से बाहर आने के कुछ ही दिनों में उन्होंने फिर से ठगी के अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए हैं।

आधी फीस में एडमिशन बन रहा नया जाल

सूत्रों के अनुसार, जाफरी द्वारा निकाले गए विज्ञापन में वादा किया गया है कि नामी संस्थान में छात्र-छात्राओं को आधी फीस पर प्रवेश दिया जाएगा, वह भी सीमित सीटों के नाम पर जल्दबाजी का माहौल बनाकर। यह वही पुरानी चाल है जो पहले भी कई मासूम युवाओं के करियर बर्बाद कर चुकी है। पहले से ही ठगी का शिकार हो चुके कई छात्र अब सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से दूसरों को चेतावनी दे रहे हैं कि वे इस जाल

में न फंसें।

अब नहीं चलने वाला जाफरी मॉडल

इस बार स्थिति पहले जैसी नहीं है। बरेली और आसपास के इलाके के छात्र-छात्राएँ अब जागरूक हो चुके हैं। पहले की तरह वे झूठे वादों और आकर्षक ऑफर्स के जाल में नहीं फंस रहे हैं। सोशल मीडिया पर छात्रों ने अभियान शुरू कर दिया है और जाफरी की सच्चाई उजागर कर रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि अगर प्रशासन सख्त कदम न उठाए, तो ऐसे जालसाज फिर से निर्दोष युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे।

शिक्षा विभाग और पुलिस प्रशासन से मांग की जा रही है कि शेर अली जाफरी और उनके

गिरोह की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

प्रशासन पर उठ रहे सवाल

यह गंभीर सवाल है कि जिस व्यक्ति पर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं और जिसकी संपत्ति जब्त की जा रही है, वह खुलेआम अखबारों में विज्ञापन कैसे दे पा रहा है? क्या प्रशासन अब भी सो रहा है या फिर कोई अंदरूनी साठगांठ इस खेल को चालू रखे हुए है? शेर अली जाफरी को वापसी से एक बार फिर बरेली में शिक्षा जगत को शकसांर कर दिया है। मगर अब वक्त बदल गया है, छात्र अब जागरूक हैं और जनता को चाहिए कि ऐसे फर्जी संस्थानों और उनके संचालकों से दूर रहें और दूसरों को भी सावधान करें।

थाना दिवस पर कुल 22 प्रार्थना पत्र फरियाद के लिए आए



अनूप कुमार

उत्तर प्रदेश: अहौरा मिजापूर में शनिवार को थाना परिसर में थाना प्रभारी अजय सेठ की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें शासन की ओर से नायब तहसीलदार गरिमा सिंह को फरियादियों के फरियाद सुनने के लिए लाया गया था। तीन प्रार्थना पत्र एसपी कार्यालय से थाना में

प्रेषित किया गया था तथा 19 प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय फरियादियों द्वारा लाया गया। जिसमें एक प्रार्थना पत्र का निस्तारण तुरंत कर दिया गया तथा अन्य प्रार्थना पत्रों का निस्तारण हेतु नायब तहसीलदार ने सक्षम विभाग के कर्मियों को देते हुए त्वरित निस्तारण हेतु आदेश भी दिया। इस दौरान क्षेत्रीय राजस्वकर्मी एवं फरियादी उपस्थित रहे।

जाटवास मोड़ से कैंची मोड़ तक 61 पौधरोपण कार्यक्रम किया गया

मेनपाल, हरियाणा: शनिवार सुबह जाटवास मोड़ से कैंची मोड़ तक 148बी डिवाइडर पर 61 पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। ग्राम जाटवास के पूर्व सरपंच रामनिवास ने अपने माता-पिता की पुण्य स्मृति में पौधों की व्यवस्था की और इनकी देखभाल स्वयं करेंगे। पौधों में 13 बोटल पाम, 17 अशोक, 21 कनेर एवं 10 कोनोकारपस के पौधे शामिल हैं। पौधरोपण कार्यक्रम में विधायक कंवर सिंह यादव मौजूद रहे।विधायक कंवर सिंह यादव ने बताया कि बारिश के दौरान हर ईसान को एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए।इसके साथ साथ देखभाल भी होनी चाहिए।समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी से ही स्वच्छ, सुंदर एवं हरित महेंद्रगढ़ का निर्माण संभव है।स्वस्थ जीवन के लिए हरियाली जरूरी है।

विधायक ने न केवल पौधरोपण



को बढ़ावा दिया बल्कि स्थानीय समुदाय की भागीदारी और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश भी फैलाया है।एक स्वस्थ एवं सुरक्षित पर्यावरण के बिना मानव समाज की कल्पना अधूरी है। पृथ्वी ग्रह पर ही मानव जीवन संभव है इसलिए इसे जीने लायक बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है।पेड़- पौधे हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है।सरकार द्वारा

चलाए जा रहे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अपनी भागीदारी भी सुनिश्चित करे।राष्ट्रीय सेवा योजना संयोजक प्रो. सोमवीर सिवाच ने बताया कि पौधरोपण कार्यक्रम में एसडीएम महेंद्रगढ़ अनिल कुमार एवं राजकीय महाविद्यालय महेंद्रगढ़ की प्राचार्य डॉ. पूर्णप्राभा के मार्गदर्शन में भी करवाए जा रहे है।ग्रामीणों में भी आग्रह किया कि वे पौधों को बच्चों

शाक्य समाज की मांगो को लेकर मुख्यमंत्री से मिले रमेश शाक्य



रमेश कुमार

हरियाणा: शाक्य सेवा समिति फतेहाबाद के अध्यक्ष रमेश शाक्य गतदिवस हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी से उनके निवास स्थान चंडीगढ़ में मिलकर शाक्य समाज की मुख्य मांगे रखीं। रमेश शाक्य ने बताया कि शाक्य समाज पिछड़ा हुआ है इसलिए उन्होंने जिला फतेहाबाद के लिए कई प्रकार की समाजहित की मांगे रखीं ! इसके अलावा हरियाणा

स्तर के लिए भी शाक्य समाज को उनके हको के लिए लिखा ! रमेश शाक्य ने कहा कि नायब सैनी एक मिलसार मुख्यमंत्री है और सब की पूरे ध्यान और अच्छे से बात सुनते हैं और मांगो को पूरा करवाते है ! रमेश शाक्य ने बताया कि बहुत जल्द शाक्य समाज का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री से मुलाकात करेगा ताकि समाज की मांगो को मुख्यमन्त्री के समक्ष रखा जा सके ! इस मौके पर अन्य समाज बंधु मौजूद रहे !

रामकेश विश्वकर्मा

उत्तर प्रदेश: बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्नपूर्णा भवनों हेतु वरीयता सूची निर्धारण एवं भूमि चिन्हांकन की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट - निर्देश दिए कि चिन्हांकन का कार्य एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाए। साथ ही, पूर्ति निरीक्षकों को आदेश दिया गया कि वे तीन दिनों के भीतर चिन्हित स्थलों का स्थलीय सत्यापन कर आख्या प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता सूची की सभी 479 स्थलों पर भूमि चिन्हित कर सुरक्षित की जाए। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य के सापेक्ष अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई।



ज्ञात हो कि वर्तमान में प्रदेश सरकार एफसीआई के गोदामों से सीधे उचित दर दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने की व्यवस्था को लागू कर रही है। लेकिन संकरी गलियों में स्थित दुकानों तक भारी वाहनों से खाद्यान्न पहुंचाना चुनौतीपूर्ण होता है। इसी को देखते हुए शासन द्वारा अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण चरणबद्ध रूप से सरकारी खर्चें पर कराया जा रहा है, जिससे उचित

दर की दुकानों को मुख्य सड़कों के पास स्थानांतरित किया जा सके और राशनकार्डधारकों को अधिक सुविधा मिल सके। गाजीपुर जनपद में वित्तीय वर्ष 2023-24 के अंतर्गत निर्धारित 75 अन्नपूर्णा भवनों में से 68 भवनों का निर्माण पूर्ण हो चुका है, जबकि 2024 25 के लक्ष्य के तहत 31 भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने राशनकार्ड

सत्यापन कार्य की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अपात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा योजना से हटाकर पात्र परिवारों को जोड़ना अति आवश्यक है, जिससे योजनाओं का वास्तविक लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचे।

इस दिशा में सभी खंड विकास अधिकारियों (इंड्र) को निर्देश दिए गए कि वे सत्यापन कार्य में तेजी लाएं और निर्धारित समयसीमा में इसे पूर्ण करें। जिलाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकारी योजनाओं की गुणवत्ता, पारदर्शिता और लाभ वितरण सुनिश्चित करने के लिए भूमि चिन्हांकन, भवन निर्माण और राशन सत्यापन जैसे कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उपद्रवियों ने जलन में पेंड को सुखाने के लिए उसकी जड़ों में डाला जहरीला केमिकल



कुछ बदमाशों, उपद्रवियों ने बिना किसी कारण के विषय संपत्ति के अंदर और सामने वृक्षों की जड़ों के पास जहरीला एसिड और रसावन डाल दिया था, जिससे वृक्षों को नुकसान पहुंचा, जिससे वे सूख गए

और मर गए। इसके लिए जब सीसीटीवी की जाँच की गई, तो पाया गया कि 06/07/2025 को दोपहर 12.55 बजे, 3 बदमाश पेड़ों के तने के पास एक गड्ढा खोद रहे थे और कुछ जहरीला रसावन/एसिड

एक नजर

कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के प्रयासों से सर्किट हाउस निर्माण को मिली मंजूरी

रियाज मोहम्मद खान

मध्य प्रदेश: पेटलावद में सर्किट हाउस निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति कैबिनेट मंत्री निर्मला भूरिया के प्रयासों से मिली मंजूरी महिला एवं बाल विकास विभाग की कैबिनेट मंत्री सुश्री भूरिया के सतत प्रयासों से पेटलावद क्षेत्र में सर्किट हाउस निर्माण की लंबे समय से चली आ रही मांग को आखिरकार मंजूरी मिल गई है लोक निर्माण विभाग की स्थायी व्यय समिति की 289 वीं बैठक में 407.५82 लाख रुपये की लागत से सर्किट हाउस निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया कि पेटलावद क्षेत्र में सर्किट हाउस की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही थी शासन स्तर पर इस संबंध में मांग रखी गई थी जिसे स्वीकृति मिलना क्षेत्रवासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है उन्होंने कहा कि अब शीघ्र ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा इस अवसर पर सुश्री ने मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके सहयोग से ही यह स्वीकृति संभव हो पाई है

कोचिंग सेंटर्स पर एसडीओपी व पुलिस का निरीक्षण,छात्रों की सुरक्षा को लेकर दी सख्त हिदायतें



अजय सिंह तोमर/मध्य प्रदेश: पोरसा शहर में कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए एसडीओपी अंबाह रवि सिंह भदौरिया व थाना प्रभारी पोरसा रामनरेश सिंह यादव ने शुक्रवार को पोरसा पुलिस बल के साथ शहर के विभिन्न कोचिंग सेंटर्स का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोचिंग संचालकों को सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने, छात्रों के आई-कार्ड बनवाने एवं हाजिरी रजिस्टर में नियमित उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही, कोचिंग के आसपास अनावश्यक रूप से घूम रहे युवाओं को समझाइश देकर क्षेत्र से हटाया गया और भविष्य में अनुशासन बनाए रखने की चेतावनी दी गई।

निरीक्षण आरबीएस स्कूल वाली गली, मंडी रोड, पुतु राम स्कूल गली, संजय स्कूल गली सहित एक दर्जन से अधिक कोचिंग संस्थानों में किया गया। इस दौरान दुर्गेश सिंह भदौरिया, नाथुराम शर्मा, किशन सिंह, शिवम यादव, पुष्पेंद्र सिंह तोमर, मनोज सिंह, धीरज सिंह और आर.डी. इंदौरिया सहित पुलिस टीम मौजूद रही। एसडीओपी भदौरिया ने कहा कि, "छात्रों की सुरक्षा सर्वोपरि है, कोचिंग संस्थानों को नियमों का पालन करना होगा, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी।"

व्यक्ति द्वारा अपने दोस्त की हत्या के मामले में न्यायालय ने सुनाया अपना फैसला



रामकेश विश्वकर्मा/उत्तर प्रदेश: अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शक्ति सिंह की अदालत ने आरोपी धनंजय उर्फ करिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मामला 7 दिसंबर 2014 का है। शेरपुर कला गांव के कवींद्र नाथ राय ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि गांव के पप्पू चौधरी और धनंजय उर्फ करिया अच्छे दोस्त थे। दोनों साथ रहते और खाते-पीते थे। किसी बात एडीजे प्रथम की अदालत ने सुनाई सजा वर्ष 2014 में भांवरकोल थाना क्षेत्र का मामला

आरोपी ने कुल्हाड़ी से मारकर की थी दोस्त की हत्याको लेकर दोनों में विवाद हो गया। इसी दौरान धनंजय ने कुल्हाड़ी से पप्पू चौधरी पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। जब कवींद्र नाथ राय बचाने गए तो आरोपी ने उन पर भी हमला किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302, 323 भादवि और 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जांच के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों को पेश किया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने धारा 302 में आजीवन कारावास और 25,000..

गला का हिस्ट्रीशीटर आम शांति भंग में गिरफ्तार 12 बोर के 19 कारतूस बरामद



उदय लाल पुष्करणा (जोशी)

राजस्थान: चित्तौड़गढ़ ढूंगला पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र में आम शांति भंग करने एवं आर्म्स एक्ट में थाना ढूंगला के हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार कर 12 बोर बंदूक के 19 जिंदा कारतूस एवं एक तलवार बरामद की। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने बताया कि एसपी सरीता सिंह के निर्देशन में एवं डीएपी बड़ी सादड़ी देशराज कुलदीप के प्रवेक्षण में थाना अधिकारी ढूंगला अमृतलाल उपनिरीक्षक व टीम द्वारा 7 जुलाई को रात्रि को थाना क्षेत्र के करवा ढूंगला में भाना खेड़ी जाने वाले रोड स्थित निमाणांभीन रामेश्वर महादेव मंदिर के क्षतिग्रस्त मामले की घटना के बाद थाना क्षेत्र में धारा 163 की पालना में नाकाबंदी की जा रहे थी। नाकाबंदी के दौरान ढूंगला निवासी 48 वर्षीय कालू खान पुत्र दलैत खान को बिना अनुज्ञापत्र के कुल 19 नंग 12 बोर बंदूक के राउंड एवं धारदार नगी छूरी सहित गिरफ्तार कर हथियार व एम्बुनिशन जबरन किया जाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। गिरफ्तार आरोपीय न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया जाकर प्रकरण अग्रिम अनुसंधान जारी है।

प्राणी, समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी व अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। एसपी डॉ. ईरज राजा ने कहा कि पुलिस को प्राथमिकता जनसुरक्षा, कानून व्यवस्था की मजबूती और अपराधों पर पूर्ण नियंत्रण है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपेक्षा जताई कि वे जनहित में पारदर्शी और संवेदनशील पुलिसिंग को धरातल पर उतारने में कोई कसर न छोड़ें।

संपादकीय

सत्ता की खातिर हिंदी विरोध की राजनीति

देश में गरीबी, भुखमरी, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं तथा चहुंमुखी विकास जैसे मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के आधार पर सत्ता पाने के सस्ते प्रयासों को देश के मकदाताओं ने कई बार नकार दिया है। चूंकि देशहित और विकास से जुड़े मुद्दों पर राजनीति करने के लिए समझ और योजना चाहिए, इसके विपरीत भावनात्मक मुद्दे को कुरेद कर समाज को बांटने में जोर नहीं पड़ता, इसलिए नेताओं का प्रयास यही रहता है कि सत्ता की खातिर ऐसे मुद्दों को भुनाया जाए। महाराष्ट्र में हिंदी को मुद्दा बना कर ऐसे ही प्रयास किए गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंग्रेजी को पूरे अमरीका में अनिवार्य किया है। इस आदेश से कहा गया कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्दिष्ट भाषा एकीकृत और सामंजस्यपूर्ण समाज का मूल है। इससे संयुक्त राज्य अमरीका ऐसे नागरिकों से मजबूत होता है जो एक साझा भाषा में विचारों का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान कर सकते हैं। इसके विपरीत हिंदी को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना के दोनों गुट राजनीति चमकाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए उन्हें हिंसा से भी परहेज नहीं है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का प्रयास है कि अमरीका में अंग्रेजी की तरह भारत में भी एक ऐसी भाषा होनी चाहिए, जिसे देश की एक सर्वमान्य भाषा बनाया जा सके। इसी प्रयास के तहत मौजूदा शिक्षा प्रणाली में हिंदी को अनिवार्य किया गया है।

महाराष्ट्र में भाजपा से सत्ता हासिल करने के लिए शिव सेना के दोनों गुटों ने हिंदी विरोध को हथियार बना लिया है। महाराष्ट्र में ठाकरे बंधुओं यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का लगभग 20 साल बाद ऐतिहासिक पुनर्मिलन हुआ। उद्धव और राज ठाकरे, जो 2005 में मालवम विधानसभा उपचुनाव के बाद से एक साथ मंच पर नहीं दिखे, उन्होंने मराठी भाषा और अस्मिता के लिए एकजुट होकर भाजपा नीत महापुति सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम एक साथ आए हैं और अब एक साथ रहेंगे। राज ठाकरे ने सरकार पर मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश का भी आरोप लगाया और मराठी अस्मिता को कमजोर करने की साजिश का भी जिक्र किया तथा यह तक कह दिया कि यदि कोई मराठी का विरोध करे तो कान के नीचे बजा दो। यानी थप्पड़ वाली राजनीति महाराष्ट्र में एक बार फिर से जोर पकड़ सकती है। यह रैली मूल रूप से 16 अप्रैल 2025 को जारी सरकारी आदेश (जीआर) के खिलाफ विरोध के रूप में प्रस्तावित थी, जिसमें हिंदी को कक्षा 1 से 5 तक अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था।

–ललित गर्ग–

बिहार में मतदाता सूची सुधार पर सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी सिर्फ एक न्यायिक फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र के मूल्य को पुष्ट करने वाला ऐतिहासिक एवं प्रासंगिक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूची की समीक्षा के लिए आधार, राशन और वोटर कार्ड को भी मान्यता देने का सुझाव देकर आम लोगों की मुश्किल हल करने की कोशिश की है। इससे प्रक्रिया आसान होगी और आशंकाओं को कम करने में मदद मिलेगी। बेपत्त, फर्जी नाम मतदाता सूची में नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसे अभियानों के दौरान आयोग का जोर ज्यादा से ज्यादा नाम वोटर लिस्ट से निकालने के बजाय, इस पर होना चाहिए कि एक भी नागरिक चुनावी रूप का लेजिस्लेशन से वंचित न रह जाए। विपक्ष को चाहिए कि वह इस फैसले को राजनीतिक हार न माने, बल्कि इसे एक अवसर माने, जनविश्वास अर्जित करने का, लोकतंत्र में आस्था बढ़ाने का और सबसे जरूरी, राष्ट्रहित को राजनीति से ऊपर रखने का। मतदाता सूची में विशेष गहन पुरीकरण (एसआईआर) का कार्य केवल बिहार ही नहीं, देश के अन्य राज्यों में प्राथमिकता के आधार पर प्रांरध करना चाहिए।

–संजय गोस्वामी–

आज सब अपना देखते हैं यही खर्ज है आज महंगाई में मिडिल क्लास का जीना ह्राम हो गया है सैलरी लगता खुब मिलता है लेकिन खर्च भी बढ़ता जा रहा है 100 रूप का आज क्या वैल्यू है उसपर सब्जी का फल का रेट देखिए अब वो जमाना गया कि कैसे भी एडजस्ट करते थे और पढ़ाई भी सस्ती थी सब्जियाँ फल तो घर में ही उगा लेते थे और काम भी चल जाता था अब बिगबास्केट, जेटो, ग्रोफ़र जैसी तमाम ग़्रोसरी से लेकर फल सब्जियाँ देती है घर पर ही जो ताजी नहीं मिलती और बापस करने पर तमाम तरह के फोटो रिटर्न्स नहीं होगा और उठा उठा महसूस समान दे रहा है किसी ना फंगस लगा हुआ मिला और बार बार ऐसा होने पर अकाउंट ही लॉक कर दिया दरअसल मैं ऑनलाइन के चक्कर में नहीं रहता हूँ लेकिन ऐ आज फॉमिली की पसंद बन गई है पहले सब्जी खरीदने बाजार निकलते थे उससे कई गुना सस्ता समान आज भी आप सब्जियाँ बाजार से खरीद कर देखें इससे आपके दो फायदा होगा आपका घुमना भी होगा और वहाँ भी जो अच्छा होगा आप चुन कर लेगे और इसी बहाने फल भी

भारतीय लोकतंत्र में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सर्वोपरि होता है। चुनाव आयोग यदि चुनाव कराने को तैयार है, और इसकी जुड़ी किन्हीं प्रक्रियाओं में कोई त्रुटि या खामी है तो उसका सुधार करना संविधान सम्मत है, तो फिर इस पर प्रश्नचिन्ह लगाने का अधिकार किसी भी राजनीतिक दल को नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न जनता के मानस को उद्बेलित करता है, वह यह है कि विपक्ष बार-बार चुनावी प्रक्रियाओं, राष्ट्रीय हितों या सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी एकमत होकर विरोध करता है, या सामाजिक समीकरण तैयार नहीं हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जनता को प्रतिनिधित्व देने का अधिकार सर्वोपरि है। लेकिन त्रुटिपूर्ण या फर्जी मतदाता सूची से चुनाव कराना भी लोकतंत्र का अपमान है। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि देर-सवेर नहीं, संवैधानिक कर्तव्य को समय पर निभाना जरूरी है।

अदालत ने एसआईआर पर कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अपने इरादे

की ओर इशारा तो कर ही दिया है। अदालत ने टाइमिंग को लेकर जो सवाल उठाया, वह उचित प्रतीत होता है। बिहार में इसी साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में इतनी विस्तृत कवायद के लिए शायद उतना वक्त न मिल पाए, जितना मिलना चाहिए। बिहार में एसआईआर को लेकर जो असमंजस है, उसकी एक वजह निश्चित ही टाइमिंग है। जिनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं हैं, वे इतनी जल्दी उनका इंजाम नहीं कर पाएंगे। हालांकि आयोग ने भरोसा दिलाया है कि किसी भी व्यक्ति को भी अपनी बात रखने का मौका दिए बिना मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जाएगा। वैसे बिहार में चुनाव को देखते हुए ही फर्जी मतदाताओं की संख्या बढ़ी या तथाकथित राजनीतिक दलों ने इन फर्जी मतदाताओं को बढ़ाया है। ऐसे में इन फर्जी मतदाताओं पर कार्रवाई अपेक्षित है। यह मामला केवल बिहार तक सीमित नहीं रहना चाहिए। दूसरे राज्यों में मतदाता सूचियों की समीक्षा किस तरह होगी, वह बिहार में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। ऐसे में स्वाभाविक ही नजरे इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आखिरकार इस प्रक्रिया का कैसा

स्वरूप तय होता है?

भारतीय राजनीति में विपक्ष का कार्य सरकार की नीतियों पर निगरानी रखना है, आलोचना करना है, लेकिन वह आलोचना रचनात्मक होनी चाहिए, राष्ट्र-विरोधी नहीं। आज हम देख रहे हैं कि आर्टिकल 370 हटाना हो, नागरिकाता संशोधन अधिनियम-सीएए, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर-एनआरसी जैसे कानून हों, अहिंसध्प योजना हो, या राम मंदिर निर्माण-लगभग हर मुद्दे पर विपक्ष ने एकमत होकर विरोध किया है। चाहे चीन या पाकिस्तान से जुड़ी संवेदनशील मसले हों, या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के निर्णय, विपक्ष अक्सर उन बिंदुओं पर एक सुर में सरकार का विरोध करता है, जबकि ऐसे राष्ट्रीयता के मुद्दों पर विपक्ष को सरकार एवं देश के साथ एकजुटता दिखानी चाहिए। यह संयोग नहीं, एक दूषित राजनीतिक रणनीति बनती जा रही है कि हड़ाने सरकार करे, उसका विरोध करोह्द, चाहे मुद्दा देशहित का ही क्यों न हो। इन स्थितियों में आम जनता का हार्दिक सवाल है कि विपक्ष देश के साथ है या सिर्फ सत्ता की भूख के साथ? क्या चुनाव प्रक्रिया पर विरोध करना लोकतंत्र का मजाक नहीं है? क्या न्यायपालिका के

निर्णयों को चुनौती देना सिर्फ स्वार्थ की राजनीति नहीं? क्या राष्ट्रीय मुद्दों पर सरकार के साथ खड़े होने से विपक्ष की राजनीति कमजोर हो जाएगी? जब विपक्ष सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करता है, तो उसका नैतिक बल कमजोर होता है, और जनता का विश्वास टूटता है।

भारतीय राजनीति को अब रचनात्मक विपक्ष की जरूरत है, ऐसा विपक्ष जो सत्ता में नहीं है, फिर भी राष्ट्र के लिए सत्ता के साथ खड़ा हो सकता है। जो यह समझ सके कि लोकतंत्र सरकार और विपक्ष दोनों से चलता है, लेकिन राष्ट्र सबसे ऊपर है। बिहार में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इन बात का प्रतीक है कि संस्थाएं अभी भी न्याय और संवैधानिकता की रक्षा कर रही हैं। लेकिन विपक्ष यदि इस निर्णय पर भी नकारात्मक रवैया अपनाता है, तो यह जनता की आकांक्षाओं, लोकतांत्रिक मूल्यों और विकासशील भारत की दिशा के विरुद्ध होगा। विपक्ष को चाहिए कि वह अपनी राजनीति को जनहित से जोड़े, जनविरोध से नहीं। विपक्ष यदि राष्ट्रहित में सोचने की दिशा में खुद को परिवर्तित नहीं करता, तो वह धीरे-धीरे प्रासंगिकता खो देगा।

देश के सेना और वैज्ञानिक को सम्मान करना चाहिए

ऐ बात निकल कर आ रही है कि पाकिस्तानी सेना को टारगेट ना करने व आतंकवादी को टारगेट करने पर कुछ राफेल नस्ट हुए जबकी वहाँ की सेना ही आतंकवादी के लिए ही बनी है अतः सेना को कभी इसप्रकार की आदेश देने की जरूरत नहीं है और उनके साथ हमेशा विश्वास करना चाहिए देश सर्वोपरि है उससे किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करनी चाहिए चाहे जग कितनी लम्बी क्यों ना हो :सपनाई चेन मॅनमेंट का सही आकलन और तकनीकी पर फोकस करना चाहिए ब्रिक देशों के सम्मेलन में जाने के बाद भी अमेरिका का डॉलर ही चलने वाला है और अमेरिका की तकनिकी को अपने वैज्ञानिक द्वारा हासिल करना आखिर हम क्यों नहीं बना पा रहें है अपनी लड़ाकू विमान इसमें बीते सालों में अच्छा कार्य हुआ जैसे तेजस बना लेकिन इंजन कावेरी अमेरिका से आयात करना पड़ता है और यही सब कमजोरी का अमेरिका फायदा उठा लेता है और उधर चीन जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है जब किसी वस्तु या सेवा की मांग, उसकी आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो कीमतें बढ़ जाती हैं। :कच्चे माल, श्रम या परिवहन की लागत में वृद्धि से भी कीमतें बढ़ सकती हैं।

अमेरिका में होने वाले आयात पर भी टैरिफ की बढ़ी हुई नई दरें लागू किये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बंध में अमेरिकी राष्ट्रपति ने इन 14 देशों के राष्ट्रध्यक्षों को पत्र भी लिखा है। इस सूची में भारत का नाम शामिल नहीं है।

पूर्व में अमेरिका द्वारा चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ की घोषणा की गई थी। चीन ने भी अमेरिका से होने वाली आयातित वस्तुओं पर लगभग उसी दर पर टैरिफ लागू करने की घोषणा कर दी थी। साथ ही, चीन ने विभिन्न देशों को दुर्लभ खनिज पदार्थों (रेयर अर्थ मिनरल) के निर्यात पर रोक लगा दी थी। अमेरिका में चीन के इस निर्णय का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। जिसके दबाव में अमेरिका ने चीन के साथ व्यापार समझौता करते हुए चीन से आयात होने वाली विभिन्न वस्तुओं पर टैरिफ की दरों को तुरंत कम कर दिया। अमेरिका द्वारा इसी प्रकार का एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता ब्रिटेन के साथ भी सम्पन्न किया जा चुका है। पूर्व में, ट्रम्प प्रशासन ने 90 दिवस की अवधि में 90 देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने की बात कही थी तथा 90 दिवस की समयावधि 9 जुलाई को समाप्त होने के पश्चात ही केवल दो देशों ब्रिटेन एवं चीन के साथ ही द्विपक्षीय व्यापार समझौते सम्पन्न हो सका है। भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया जा चुका है परंतु इसकी अभी तक घोषणा नहीं की गई है। द्विपक्षीय समझौते के लिए शेष देशों पर दबाव बनाने की दृष्टि से ही इन देशों से अमेरिका को होने वाले आयात पर टैरिफ की दरों को एक बार पुनः बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है और इन बढ़ी हुई दरों को 1 अगस्त 2025 से लागू करने की योजना बनाई गई है।

वैश्विक स्तर पर अमेरिका द्वारा छेड़े गए इस टैरिफ युद्ध से निपटने के लिए भारत एक विशेष रणनीति के अंतर्गत कार्य करता हुआ

टैरिफ युद्ध अमेरिका पर ही भारी पड़ सकता है

–प्रहलाद सबनानी–

पूर्व में अमेरिका द्वारा

चीन से आयात होने वाले

उत्पादों पर भारी भरकम

टैरिफ की घोषणा की गई

थी। चीन ने भी अमेरिका

से होने वाली आयातित

वस्तुओं पर लगभग उसी

दर पर टैरिफ लागू करने

की घोषणा कर दी थी।

साथ ही, चीन ने विभिन्न

देशों को दुर्लभ खनिज

पदार्थों (रेयर अर्थ

मिनरल) के निर्यात पर

रोक लगा दी थी।

अमेरिका में चीन के इस

निर्णय का बहुत गहरा

प्रभाव पड़ा था। जिसके

दबाव में अमेरिका ने चीन

के साथ व्यापार समझौता

करते हुए चीन से आयात

होने वाली विभिन्न

वस्तुओं पर टैरिफ की

दरों को तुरंत कम कर

दिया।

मतदाता सूची में सुधार पर सुप्रीम सहमति सराहनीय

कृषि वैज्ञानिक बनकर संवारे भविष्य

भारत विश्व के प्रमुख कृषि प्रधान देशों में से एक है। देश के आर्थिक विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि विज्ञान-आधारित, उच्च-प्रौद्योगिकीय क्षेत्र है तथा इससे संबंधित रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं। ये हैं - पशु और पादप शोधकर्ता, खाद्य वैज्ञानिक, वस्तु ब्रोकर, पोषणविद, कृषि पत्रकार, बैंकर्स, बाजार विश्लेषक, बी बि व्यावसायिक, खाद्य संसाधक, वन प्रबंधक, वन्यजीव विशेषज्ञ आदि। कृषि अनुसंधान और शिक्षा कृषि विश्वविद्यालयों, संस्थानों तथा कृषि शिक्षा और पशुचिकित्सा विज्ञान महाविद्यालयों द्वारा संचालित की जाती है।



कृषि विज्ञान एक व्यापक बहुविषयक क्षेत्र है, जिसमें प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक विज्ञान हिस्से हैं, जिन्हें कृषि व्यवहार तथा इसे समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस क्षेत्र में निम्नलिखित पर अनुसंधान एवं विकास कार्य किए जाते हैं- उत्पादन तकनीकें (जैसे कि, सिंचाई प्रबंधन, अनुशसित गाइड्रोजन इनपुट्स) गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से कृषि उत्पादन में सुधार (जैसे कि सूखा झेलने वाली फसलों तथा पशुओं का श्वसन, नए कीटनाशकों का विकास, खेती-संवेदन प्रौद्योगिकियां, फसल वृद्धि के सिमुलेशन मॉडल, इन-वाइट्रो सेल कल्चर तकनीकें) प्राथमिक उत्पादों का अंतिम-उपभोक्ता उत्पादों में परिवर्तन (जैसे कि डेरी उत्पादों का उत्पादन, संरक्षण और पैकेजिंग) विपरीत पर्यावरणीय प्रभावों की रोकथाम तथा सुधार जैसे कि मृदा निम्नीकरण, कचड़ा प्रबंधन, जैव-पुनः उपचार)

सैद्धान्तिक उत्पादन पारिस्थितिकी, फसल उत्पादन मॉडलिंग से संबंधित परंपरागत कृषि प्रणालियां, कई बार इसे जीविका कृषि भी कहा जाता है, जो विश्व के सर्वाधिक गरीब लोगों का भरण-पोषण करती है। ये परंपरागत पद्धतियां काफी रुचिकर हैं क्योंकि कई बार ये औद्योगिक कृषि की बजाए यादा प्राकृतिक पारिस्थितिकी व्यवस्था के साथ समाकलन का स्तर कायम रखती हैं जो कि कुछ आधुनिक कृषि प्रणालियों की अपेक्षा यादा दीर्घकालिक होती हैं।

कृषि वैज्ञानिकों के विशेषज्ञता के क्षेत्र के अनुरूप उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति में भिन्नता रहती है।

खाद्य विज्ञान - खाद्य वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद सामान्यतः खाद्य संसाधन उद्योग, विश्वविद्यालयों या संघीय सरकार में नियुक्त किए जाते हैं। वे स्वास्थ्यपरक, सुरक्षित



और सुविधाजनक खाद्य उत्पादों की उपभोक्ताओं की मांग को पूरा करने में मदद करते हैं।

पादप विज्ञान - पादप विज्ञान में कृषि विज्ञान, फसल विज्ञान, कीट-विज्ञान तथा पादप प्रजनन को शामिल किया गया है।

मृदा विज्ञान- इसके अंतर्गत काम करने वाले व्यक्ति पौधों या फसल विकास से जुड़ी मिट्टी के रासायनिक, भौतिकीय, जैविकीय तथा खनिजकीय संयोजन का अध्ययन करते हैं। वे उर्वरकों, जुताई के तरीकों और फसल चम को लेकर विभिन्न प्रकार की मिट्टी के प्रत्युत्तरों का अध्ययन करते हैं।

पशुविज्ञान- पशु वैज्ञानिकों का कार्य है मांस, कुकुर, अण्डों तथा दूध के उत्पादन तथा प्रोसेसिंग के बेहतर और अधिक कारगर तरीकों का विकास करना। डेयरी वैज्ञानिक, पशु प्रजनक तथा अन्य संबद्ध वैज्ञानिक घरेलू फार्म पशुओं के आनुवंशिकी, पोषण, प्रजनन, विकास तथा उत्पादन से जुड़े अध्ययन करते हैं।

प्रशिक्षण, अन्य योग्यताएं - कृषि वैज्ञानिकों के प्रशिक्षण की अपेक्षाएं उनके विशेषज्ञता क्षेत्र तथा किए जाने वाले कार्यों की प्रकृति पर निर्भर करती है।

अनुप्रयुक्त अनुसंधान के लिए या मौलिक अनुसंधान में सहायता के लिए कृषि विज्ञानों में बैचलर डिग्री पर्याप्त होती है लेकिन मौलिक अनुसंधान के वास्ते मास्टर्स या डॉक्टरल डिग्री अपेक्षित होती है। कॉलेज शिक्षण और प्रशासनिक अनुसंधान पदों में प्रगति के लिए सामान्यतः कृषि विज्ञान में पी-एचडी डिग्री अपेक्षित होती है।

कृषि विज्ञान में बीई करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए मौलिक पात्रता मानदंड भौतिकी, रसायन शास्त्र, गणित और वरीयतन जीव-विज्ञान विषयों के साथ 10+2 है। एक सुयोग्य कृषि इंजीनियर बनने के लिए किसी के भी पास कृषि इंजीनियरी में स्नातक डिग्री (बीई/बीटेक) या कम से कम डिप्लोमा होना चाहिए। अनुसंधान के क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति कृषि अनुसंधान वैज्ञानिक (एआरएस) बन सकता है। इन पदों पर भर्ती संयुक्त प्रवेश परीक्षा के जरिए की जाती है। एआरएस नेट पी-एचडी. उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को लेक्चरशिप तथा स्कॉलरशिप प्रदान करने हेतु आयोजित की जाती है।

दूसरा विकल्प कृषि विकास अधिकारी (एडीओ) बनने का है,

जो पद खण्ड विकास अधिकारी के समकक्ष होता है। इन पदों पर भर्ती प्रवेश परीक्षा के आधार पर की जाती है।

तीसरे आपके पास निजी क्षेत्र के संगठनों में अनुसंधान वैज्ञानिक के पद पर आवेदन करने का विकल्प होता है। वहां पर आपकी सेवाएं

निजी प्रयोगशालाओं में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित योग्यता डॉक्टरल स्तर की अर्थात पी-एचडी. है।

बी.एससी. करने के उपरांत आप बैंकों, वित और बीमा कम्पनियों की नौकरियों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में स्नातकोत्तरों के लिए फील्ड अधिकारियों, ग्रामीण विकास अधिकारियों तथा कृषि और परिवीक्षा अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करते हैं। इनके अलावा फार्म प्रबंधन, भूमि मूल्यांकन, ग्रेडिंग, पैकेजिंग तथा लेबलिंग के क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों में भी विपणन और बी, परिवहन, फार्म उपयोगिता, भण्डारण आदि के क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।

कृषि विज्ञान में पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संस्थान

- अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय - कृषि केंद्र, अलीगढ़-202002 (उ.प्र.)
- चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय (उ.प्र.)
- डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ कृषि इंजीनियरी संकाय, डाकघर कृषि नगर, अकोला-444104
- गुजरात कृषि विश्वविद्यालय कृषि संकाय, सरदार कृषि नगर-385506, जिला बनासकांठा (गुजरात)
- इंदिरा गाँधी कृषि विश्वविद्यालय कृषक नगर, रायपुर-492006 (छत्तीसगढ़)
- जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि इंजीनियरी संकाय, कृषि नगर, अगरतला, जबलपुर-482004
- केरल कृषि विश्वविद्यालय कृषि संकाय, वेल्लनिकाड़ा, त्रिशूर-680654 (केरल)
- उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्व-विद्यालय कृषि संकाय, भुवनेश्वर, खुर्दा-751003 (उड़ीसा)।



जब बादल गरजने लगते हैं तो स्टीफन थर्न की नज़रें तुरंत अपने कम्प्यूटर पर गड़ जाती हैं। यह इलेक्ट्रीकल इंजीनियर तुरंत जानना चाहते हैं कि कहीं आसमानी बिजली गिराने वाला तूफान तो आने वाला नहीं है। उनकी तकनीक ने उन्हें कभी निराश नहीं किया है। वह बहुराष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पनी सीमन्स की 'द लाइटनिंग सर्विस' नामक जर्मन फर्म के प्रमुख हैं जो जर्मनी में प्रतिवर्ष औसतन 10 लाख बार आसमानी बिजली के कौंधने को दर्ज करती है। फर्म का जर्मन नाम 'ब्लित्ज़डेन्स्ट' है। जर्मन भाषा में 'ब्लित्ज़' का अर्थ बिजली कौंधना होता है। जर्मनी भर में स्थापित 16 निगरानी केंद्र देश में बिजली कौंधने की सभी घटनाओं को दर्ज करने के लिए काफी हैं। अपनी सहयोगी कम्पनियों के साथ मिल कर सीमन्स यूरोप में ऐसे कुल 150 निगरानी केंद्र चला रही है। इन आंकड़ों की जरूरत इलेक्ट्रिसिटी कम्पनियों, हवाई अड्डों, बीमा कम्पनियों एवं सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजकों को पड़ती है जो इस सूचना के लिए फर्म को फीस देते हैं। आसमानी बिजली को दर्ज करना सरल है। इसकी हर कौंध के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें पैदा होकर तेज रफ्तार से सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। आसमानी बिजली की निगरानी करने वाले केंद्र इन तरंगों को 600 किलोमीटर दूर से भी पहचान सकते हैं। स्टीफन के अनुसार इन्हें और भी दूरी से दर्ज किया जा सकता है। वह पुर्तगाल के आकाश में चमकने वाली बिजली की कौंध को जर्मनी के कार्लरुहे निगरानी केंद्र से दर्ज कर चुके हैं। जब आसमानी बिजली को कम से कम दो केंद्रों में दर्ज किया जाता है तो उनके समय तथा दूरी का आकलन करके स्थान का पता लग जाता है। जितने अधिक निगरानी केंद्र होंगे

आसमानी बिजली के कौंधने के स्थान का पता उतनी ही सटीकता से लगाया जा सकता है। फिलहाल फर्म की सटीकता 200 से 700 मीटर तक है। बिजली कौंधने के स्थान में सबसे अधिक रुचि ओवरहैड पावर लाइन ऑपरिटर को होती है। उनकी कोई तार टूटते ही वह जानना चाहते हैं कि इसकी वजह कहीं आसमानी बिजली का गिरना या पेड़ का गिरना तो नहीं है। यदि इलाके में बिजली गिरने की पुष्टि हो जाए तो तारों को जल्द से जल्द जोड़ा जा सकता है जबकि पेड़ गिरने की सूरत में उसे ठीक करने में अधिक समय लगता है। बीमा कम्पनियां बिजली गिरने से होने वाले नुकसान के दावों की पड़ताल के लिए इस सूचना की मदद लेते हैं। अक्सर आसमान से गिरने वाली बिजली की वजह से सीधा नुकसान नहीं होता है बल्कि इसकी वजह से वोल्टेज में होने वाली अत्यधिक वृद्धि के कारण होता है। इससे अढ़ाई किलोमीटर के दायरे में विद्युत उपकरणों में शॉर्ट-सर्किट हो सकता है। जर्मनी में हर साल बिजली गिरने से होने वाले नुकसान के 3 से 5 लाख दावे किए जाते हैं। दावों की राशि करीब 25 अरब रुपए होती है। बीमा कम्पनियां 'द लाइटनिंग सर्विस' से हासिल बिजली गिरने की घटनाओं के आंकड़ों की जांच करके तुरंत पता लगा लेती हैं कि दावा असली है या फर्जी। वैसे फर्म केवल आसमानी बिजली की कौंध को दर्ज ही नहीं करती है, उसके आंकड़े चेतावनी जारी करने के काम भी आते हैं। कम्पनी के अनेक ग्राहक हैं जिन्हें समय रहते इलाके में बिजली चमकने या तूफान आने की पूर्व सूचना मिलती है और वे अपने बिजली के उपकरणों को बंद करके नुकसान होने से बच जाते हैं।

महिलाएं विदेशों में जॉब के साथ-साथ बेहतर सैलरी के लिए अपनाएं यह कैरियर

डॉक्टरों को दूसरा भगवान कहा जाता है क्योंकि मरीजों को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी इन्हीं पर होती है लेकिन इस महत्वपूर्ण कार्य में नर्स की भूमिका को भी नकारा नहीं जा सकता है। देखा जाए तो मरीजों की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर ही होती है। तभी तो इन्हें सभी प्यार से सिस्टर भी कहते हैं। भारतीय सिस्टर विदेश का भी रुख करने लगी हैं क्योंकि विदेशों में इन्हें जॉब के साथ-साथ बेहतर सैलरी भी मिलने लगी है।

जॉब ऑप्शन

डीपीएमआई की प्रिंसीपल डॉक्टर अरुणा सिंह के मुताबिक आप 10वीं और 12वीं करने के बाद भी नर्सिंग के कोर्स में दाखिला ले सकती हैं। इस कोर्स की सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद आपके लिए जॉब के कई रास्ते खुल जाते हैं। दरअसल, इस क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज जॉब की कोई कमी नहीं है। आप हॉस्पिटल, नर्सिंग होम्स, वलीनिक और हेल्थ डिपार्टमेंट, ओल्ड एज होम्स, मिलिट्री हेल्थ सर्विस, स्कूल्स, रेलवे, पब्लिक सैक्टर, मैडीकल डिपार्टमेंट आदि में कार्य कर सकते हैं।

विदेश में अवसर

यदि आप इस क्षेत्र से जुड़ी हैं तो आज यूरोपियन

देशों, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका और खाड़ी देशों में जॉब की असीम संभावनाएं मौजूद हैं। साथ ही इन देशों में आकर्षक सैलरी पैकेज के साथ ओवरटाइम भी मिलता है। यही वजह है कि भारतीय नर्स विदेश का रुख करने लगी हैं लेकिन यूरोप और अमरीका जाने के लिए सी.जी.एफ.एन.एस. (कमीशन ऑफ ग्रेजुएट ऑफ फॉरेन नर्सिंग स्कूल), टी.ओ.ई. एफ.एल. (टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज), टी.डब्ल्यूई. (टेस्ट ऑफ रितन इंग्लिश) और टी.एस.ई. (टेस्ट ऑफ स्पोकन इंगलिश) के एग्जाम के दौर से होकर जुड़ना पड़ सकता है।

सरकारी प्रयास

नर्सिंग एजुकेशन में व्यापक सुधार के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने की योजना है। इसके लिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने 230 जिलों की पहचान की है जहां ऑग्निलियर नर्स मिडवाइव्स (एएनएम.) और ग्रेजुएट नर्स मिडवाइव्स (जीएनएम.) इंस्टीच्यूट खोला जाएगा। इसके अलावा, चार रीजनल इंस्टीच्यूट में नर्सिंग की शिक्षा को और बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। सच तो यह है कि आज नर्स हेल्थ केयर सिस्टम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

पारिश्रमिक

नर्स की सैलरी उनकी योग्यता और अनुभव पर भी निर्भर करती है। सरकारी अस्पतालों में सैलरी 8 हजार से 15 हजार रुपए के करीब हो सकती है। लेकिन प्राइवेट और मिलिट्री नर्सिंग में कार्य करने वालों की सैलरी ज्यादा होती है।



रंगों की दुनिया में उभरते रोजगार

रंगों की दुनिया चमक-दमक से भरी होती है। इस बहुरंगी दुनिया में रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हैं। दुकान, मकान, घर और कल-कारखानों से लेकर हर छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए विभिन्न प्रकार के रंगों का इस्तेमाल होता है। रंगों के क्षेत्र में पेंट इंजीनियरिंग एक आकर्षक और बेहद फायदेमंद कैरियर है। मोटर वाहन उद्योग, विद्युत, रसायन और हल्के इंजीनियरिंग उद्योगों में भी रंगों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता है। इस प्रकार पेंट के उपयोग के क्षेत्रों में विस्तार होने के साथ-

साथ पेंट तकनीकी का भी काफी विकास हुआ है। जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के मौके बढ़े हैं। साथ ही हाल के वर्षों में पेंट की खपत भी बढ़ी है। पेंट निर्माण के क्षेत्र में न केवल देशी कंपनियों में बढ़ोतरी हुई है बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ-साथ कच्चा माल तैयार करने वाले उद्योगों में भी रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। लेकिन दूसरी इंजीनियरिंग शाखाओं की अपेक्षा पेंट इंजीनियरिंग की विस्तृत जानकारी के प्रचार-प्रसार का अभाव

है। यह क्षेत्र उन युवाओं के लिए अत्यधिक उपयोगी है जो इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं मिल पाने पर निराश हो जाते हैं। इस क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए निम्न संस्थानों से संपर्क कर सकते हैं-

- विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, जलगांव- 425 001।
- विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, अमरावती

विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र।

- जगन्नाथ रथी वोकेशनल गाइडेंस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फरगंसन कालेज कैम्पस के सामने बीएमसीसी, पुणे।
- इंडस्ट्रीयल रिसर्च लैबोरेटरी, कैनाल साउथ रोड, कोलकाता।
- विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, नाथलाल पारीख मार्ग, माटुंगा, मुंबई।
- रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जमशेदपुर, झारखंड।

